Titupati Balaji Group / Established 2009 / Ghaziabad
R.N.I No. UPBIL/2009/28691, DAVP Code: 101473

Page 8 / Price Rs. 2.00 / Ghaziabad, Sunday, 4 March 2018
Postal Registration No. UP/GBZ-80/2016-18

TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-9 Issue - 39

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad
केन्द्र एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcgzb.com

News of the Week

lkaIn dkV u bPNkeR;| dk vf/kdkj fn;k gA dkbZ Hkh 0;fDr ykbykt jkx I xfIr gkus vkj ej.kklUu fLFkfr e igpus I io funs'k n Idrk g fd mIds thouj{kd midj.k gVkdj 'kkfr I eju fn;k tk,A

Inside Ghaziabad

पेज नंबर 2
e/kcu&ckiu/kke e vk|kfxd {k= gkxk fodfIr

पेज नंबर 5
Ghaziabad couple found dead in bathroom...

TIRUPATI EYE

;kno flg ler dbZ vkjkih g, dkV e is'k

xkft;kckn % नोएडा प्राधिकरण घोटाले में बृहस्पतिवार को आरोपी मुख्य अभियंता यादव सिंह समेत कई आरोपी सीबीआइ कोर्ट में पेश हुए। बृहस्पतिवार को एक बैंक के पूर्व मैनेजर राजेश्वर सक्सेना की गवाही हुई। गवाही पूरी होने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख लगाई है। बृहस्पतिवार को विशेष सीबीआइ कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण घोटाले में सुनवाई होनी थी।

uk,Mk çkf/kdj.k ?kkVkys e tbZ dks feyh tekur

xkft;kckn % नोएडा प्राधिकरण में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में डासना जेल में बंद आरोपित जेई ओमपाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बृहस्पतिवार को जेई के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी विशेष सीबीआइ कोर्ट में जमा की। कोर्ट ने दो लाख रुपये के पर्सनल बांड व दो–दो लाख रुपये के दो जमानती पेश करने के बाद जमानत के आदेश दिए।

ekxk dk y dj Ih,evk dk Kkiu

xkft;kckn : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गाजियाबाद शाखा ने बृहस्पतिवार को सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में जिलाध्यक्ष देवब्रत चौधरी ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध अनुचित तरीके से मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्य अन्य संवर्ग से कराए जा रहे हैं। ज्ञापन में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्य संवर्ग कर्मचारियों को सौंपे जाने की मांग की गई है।

jkVjh Dyc vkQ bfnjkiqje Xykj us rhu fo|ky; cuk, LekV

i[k] iktDVj] dI;Vj] cp] V;c ykbV d vykok dbZ vU; lkeku yxk,

Xkkft;kckn % रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम ग्लौर जनपद गाजियाबाद के तीन सरकारी स्कूलों को गोद लेकर उन्हें स्मार्ट स्कूल बना रहा है। रोटरी क्लब ने स्कूलों को पंखे, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, बैंच, ट्यूबलाइट के अलावा टायलेट, शुद्ध पेयजल, साफ–सफाई व अन्य कई सुविधाएं मुहैया कराई है। रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम ग्लौर की प्रेजीडेंट रो. मनीषा भार्गव ने बताया कि क्लब द्वारा जून 2016 में साहिबाबाद गांव स्थित जूनियर व प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया था। वहीं सराय नजर अली स्थित प्राथमिक विद्यालय को जून 2015 में गोद लेकर विकास कार्य शुरू कराए। साहिबाबाद प्राथमिक व जूनियर विद्यालय को स्मार्ट बनाने के लिए दो कंप्यूटर दिए गए जिससे बच्चे स्मार्ट बन सके। इसके अलावा 11 पंखे दिए गए। वहीं स्कूल में प्रोजेक्टर लगवाया। पानी की टंकी व

सबमर्सिबल लगवाए। विद्यार्थियों व टीचर के लिए अलग–अलग टायलेट बनवाए। अब स्कूल को 20 बेंच दी जाएगी। जिससे विद्यार्थी बैंच पर बैठकर पढाई कर सके। रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम ग्लौर के चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज कुमार भार्गव ने बताया कि सराय नजर अली स्थित प्राथमिक विद्यालय को 50 बैंच, 6 पंखे, 5 ट्यूबलाइट दी गई है। इसके अलावा यहां बच्चों के लिए अलग–अलग टायलेट बनवाए गए। उन्होंने बताया कि तीनों विद्यालय को स्मार्ट बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिलता। यदि डीएम उन्हें सहयोग करें तो वे जनपद के अन्य सरकारी स्कूलों को भी गोद लेकर उनका विकास करा सकते है। डा.भार्गव ने बताया कि जिले में कुल 593 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें करीब 80 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। शहर के स्कूलों की हालत बद से बदतर है। शहर में 125 विद्यालय हैं। इनमें से अधिकांश में शौचालय, फर्नीचर, बिजली, पेयजल और हाथ धोने के इंतजाम तक नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई सरकारी स्कूलों में बालक और बालिकाओं के अलग–अलग शौचालय तक नहीं है। ऐसे में दोनों एक ही शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। स्कूलों में अलग–अलग शौचायल बनवाए जाएं। प्रशासन द्वारा स्कूलों में सुविधाएं न देने से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो रही है। प्रशासन को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम किया जा रहा है।

jk'ku forj.k e ftys dks feyk igyk LFkku

xkft;kckn : आधार से राशन वितरण के मामले में गाजियाबाद ने प्रदेश के अन्य जिलों को पीछे छोड़ दिया। फरवरी में गाजियाबाद पहले स्थान पर रहा। शामली दूसरे और हापुड़ तीसरे स्थान पर रहा। सरकार द्वारा 28 फरवरी को तय रेकिंग के आधार पर नंबर एक का स्थान दिया गया। जिले में राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का कार्य चल रहा है। इसके लिए हर महीने रिपोर्ट मांगी जाती है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी न की जा सके। इसके अलावा पात्र लोगों को हर हाल में राशन मिल सके। आधार से राशन वितरण

में जिले को पहला स्थाना मिला है। शहर में 516 राशन की दुकानें हैं। इन सभी ई–पोस मशीन हैं। इसी के आधार पर वितरण किया जा रहा है। इन दुकानों से 64 हजार 600 कार्ड धारक जुड़े हैं।

;g jfdx % गाजियाबाद 85.2 प्रतिशत, शामली 82.02 प्रतिशत, हापुड़ 80.18 प्रतिशत, फिरोजाबाद 80.04 प्रतिशत, पिलीभीत 79.7 प्रतिशत, बरेली 70.18 प्रतिशत।

Ghaziabad Development Authority seeks expert help to decongest key areas in city

GZB: The Ghaziabad Development Authority has asked the Central Road Research Institute (CRRI) to prepare a comprehensive mobility plan for three busy stretches in the city. A letter in this regard has been written by the GDA vice-chairperson to CRRI, officials said. The stretches identified by the GDA as traffic-snarl prone are from Ghanta Ghar to Bhatia More on GT Road, Modinagar along NH-58 and Indirapuram. Apart from this, the GDA has sought a feasibility report from CRRI for a multi-level parking near Swarn Jyanti Park in Indirapuram within one week. The GDA had recently signed a memorandum of understanding with CRRI for creating a comprehensive mobility plan for the entire city. Officials said it had been agreed that a short and long-term plan aimed at decongesting the city's roads would be prepared along with suggestions on changing the road design at busy intersections. "The CRRI had to submit a comprehensive mobility plan in nine months.

e/kcu&ckiw/kke e vk|kfxd {k= gkxk fodflr

xkft;kckn : गाजियाबाद में एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। यह क्षेत्र एनएच–58 पर मधुबन बापूधाम योजना में विकसित किया जाएगा। जीडीए इस औद्योगिक क्षेत्र के छोटे–बड़े सभी भूखंडों की बिक्री करने में जुट गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से गाजियाबाद में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जीडीए मधुबन बापूधाम योजना में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है। एनएच–58 पर विकसित होने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न आकार के भूखंड हैं। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि यह औद्योगिक क्षेत्र 1,14,476 वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा। इसमें से 75,674 वर्ग मीटर जमीन पर छोटे–बड़े 40 से ज्यादा प्लाट हैं। यहां बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 11,555 वर्गमीटर में पार्क भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही 27,247 वर्ग

मीटर जमीन सड़कों के लिए रखी गई है। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में 540 वर्ग मीटर से लेकर 1310 वर्ग मीटर तक के प्लाट हैं। इसके अलावा एक अस्पताल के लिए भी भूखंड रखा गया है। इस क्षेत्र में उद्योग के अलावा 15,350 वर्ग मीटर में व्यावसायिक कार्यालय, 4500 वर्ग मीटर में होटल, 9483 वर्ग मीटर में मल्टीप्लेक्स, 4550 वर्ग मीटर में आस्पताल आदि विकसित किए जाएंगे। उद्यमियों का कहना है कि एक और औद्यगिक क्षेत्र विकसित होने का लाभ सभी को होगा। यहां उद्योग और व्यावसायिक कार्यालय खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों में जहां श्रमिकों की जरूरत होगी। वहीं, बड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक कार्यालय खुलने से पढ़े–लिखे लोगों को भी रोजगार मिलने की संभावना है।

bu {k=k e g m|kx

गाजियाबाद में 15 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र पहले से हैं। इसमें मुख्य रूप से कविनगर, बुलंदशहर, साउथ साइड जीटी रोड, साहिबाबाद, मेरठ रोड, उद्योग कुंज एनएच–24, डासना, एमजी रोड (मसुरी गुलावढ़ी) ट्रॉनिका सिटी लोनी, लोनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, मुकंदनगर, पांडवनगर, अमृत स्टील कंपाउंड, आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट, मोहननगर इंडस्ट्रियल इस्टेट, पंजाब ऑल एक्सपेलर कंपाउंड, लोनी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, एक्सपेलर कंपाउंड, लोनी रोड इंडस्ट्रीयल एरिया आदि हैं।

lMd fuekZ.k e djksMk dk ?kksVkyk] gkxh tkp

xkft;kckn । नगर निगम द्वारा शास्त्रीनगर में बनवाई गई सड़क में हुए कथित करोड़ों रुपये के घोटाले में कई की गर्दन फंसना तय है। लोकायुक्त ने इस मामले की जांच का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। वेदप्रकाश अग्रवाल की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने जांच के लिए दो सदस्यों की एक टीम से जांच कराने के लिए कहा गया है। टीम ने नगर निगम से घोटाले से संबधित पत्रावली तलब भी कर ली है। टीम ने जांच करने के लिए गाजियाबाद में डेरा डाल लिया है। अवस्थापना निधि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में पौने चार करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर हुई थी। इस रकम से शास्त्रीनगर स्थित राज गैस एजेंसी के सामने की सड़क को दो से चार लेन तक चौड़ा करने, बीच में डिवाइडर बनाने, साइड में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम पूरा करने का प्रस्ताव पास हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया कि मौके पर न तो डिवाइडर बना, न इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी और न ही सड़क चार लेन चौड़ी हुई। इसके बावजूद ठेकेदार को 90 फीसदी भुगतान कर दिया गया था। चिरंजीव विहार निवासी वेद प्रकाश अग्रवाल ने इस मामले को उठाया था। उन्होंने प्रदेश सरकार को भी जांच के लिए पत्र लिखा था। शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इसके अलावा लोकायुक्त यूपी से भी शिकायत की गई। लोकायुक्त ने जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी और नगर आयुक्त सीपी सिंह को पत्र भेजा है।

dSx tehu ds lkFk dsæ ls feyus okys iSls dk Hkh fglkc ysxk

xkft;kckn : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) सूबे में विभिन्न योजनाओं के नाम पर किए गए जमीन अधिग्रहण की जांच के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले हर पैसे का हिसाब लेगा। इस बाबत भू–अर्जन विभाग से जानकारी मांगी गई है। साथ ही मुआवजा वितरण में लगाए गए कर्मचारियों की सूची तलब की है। इससे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और एनएचएआई से जुड़ी योजनाएं जांच के दायरे में आ सकती हैं। भूमि अध्याप्ति निदेशक दिग्विजय सिंह ने गाजियाबाद समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों से पिछले पांच साल दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए अधिग्रहीत जमीन के दस्तावेज मांगे हैं। यह रिकॉर्ड कैग को दिया जाना है, ताकि जमीन से जुड़ी जांच हो सके। मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे समेत कई योजनाओं की जांच कराई। इसमें दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे में 25 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा गया। कैग टीम जमीन ही नहीं विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार से मिले पैसे का भी हिसाब लेगी। भू–अर्जन विभाग से पांच साल के दौरान मिलने पैसे की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा भू–अर्जन दफ्तर में कितने अधिकारी और कर्मचारी है, कितने पद खाली हैं। मुआवजा वितरण करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया या नहीं। किस तरह किसानों को मुआवजा वितरण किया गया। यह जानकारी निर्धारित प्रारूप में भेजने के लिए कहा गया। शासन के आदेश पर भू–अर्जन विभाग दस्तावेज तैयार करने में जुटा है। एडीएम भू अर्जन का कहना है कि यह रूटीन प्रक्रिया है। शासन से सामान्य जानकारी मांगी गई है। भू–अधिग्रहण की जांच होगी इसका पता नहीं। गौरतलब है कि कैग जांच होने से कुछ अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप है। दरअसल, दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे घोटाला में एक पूर्व भू–अर्जन अधिकारी और अमीन फंस चुके है। उनके खिलाफ शासन के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दो पूर्व जिलाधिकारियों के नाम भी इस प्रकरण में जुड़ चके हैं। इसे देखते हुए कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के होश फाख्ता हैं।

Ng vkSj ftyk ls tkudkjh ekaxh

छह और जिलों के जिलाधिकारियों से भू–अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। इसमें गौतबुद्धनगर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और सीतापुर के जिले हैं। इस हिसाब से कुल 38 जिले हो गए।

vk/kkj dkMZ fyad djkus ds cgkus ;qod ls Bxh

xkft;kckn । कनावनी गांव में रहने वाले एक युवक से नौ हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। बदमाश ने आधार कार्ड लिंक कराने के बहाने बैंककर्मी बनकर युवक से उसके खाते की जानकारी ली। फिर ऑनलाइन खरीदारी कर वारदात को अंजाम दिया। कनावनी निवासी रोहित एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। रोहित ने बताया कि शनिवार शाम को उनके पास एक युवक का फोन आया। युवक ने खुद को बैंककर्मी बताते हुए आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने के लिए कहा। इस दौरान युवक ने कहा कि अगर वह तुरंत बैंकखाते और आधार कार्ड की जानकारी दे तो वह तुरंत लिंक कर देगा।

<kbZ djksM esa fcdk vkoklh; Hkw[kaM

xkft;kckn : जीडीए ने सोमवार को इंदिरापुरम ज्ञानखंड चार का आवासीय भूखंड ढाई करोड़ रुपये में नीलाम किया। इसके साथ ही ब्रिज विहार और नंदग्राम योजना की संपत्ति साढ़े तीन करोड़ रुपये में बेची गई। लंबे समय के बाद नीलामी में साढ़े तीन करोड़ की संपत्ति बिकने से जीडीए अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। जीडीए ने सोमवार को प्राधिकरण के सभाकक्ष में बहुउद्देश्यीय भवनों की संपत्तियों और आवासीय भूखंडों की नीलामी कराई। नीलामी के लिए कुल 17 संपत्तियां रखी गई थीं। इसमें इंदिरापुरम ज्ञानखंड–4 के 214.26 वर्गमीटर आवासीय भूखंड खरीदने की लोगों में रुचि दिखाई। प्राधिकरण ने इस भूखंड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य 1.07 करोड़ निर्धारित किया था, जिसे नीलामी में ढाई करोड़ में बेचा गया। इसके अलावा ब्रिज विहार योजना सेक्टर–8सी ब्लॉक में 55.86 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड 39. 22 लाख में नीलाम हुआ, इसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य 16.76 लाख निर्धारित था। नंदग्राम योजना में एलआईटी आवासीय भवन 15.68 लाख में नीलाम हुआ, इसकी न्यूनतम आरक्षित मूल्य 4.17 लाख आरक्षित किया था। इसी योजना में 115.27 वर्गमीटर का कन्वीनियेंट शॉपिंग भूखंड 45.56 लाख में नीलाम हुआ।

thMh, us lMdksa ds fdukjs ls jgsM+h&iVjh vkSj cSuj gVk,

xkft;kckn । जीडीए ने सोमवार को इंदिरापुरम की सड़कों से बैनर–पोस्टर, रेहड़ी–पटरी और खोखे हटाए गए। वहीं सड़कों के किनारे खड़े वाहनों को उठाया गया। जीडीए अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि सोमवार को इंदिरापुरम में अतिक्रमण हटाने, अवैध पोस्टर बैनर हटाने के लिए चार टीम बनी थी। काला पत्थर से शुक्रबाजार चौक तक, जयपुरिया माल से हैबीटेट सेंटर तक, आदित्य मेगा मॉल तक और अभय खंड इलाके में पोस्टर बैनर हटाने की कार्रवाई की गई।

xkft;kckn ds gksyh ,ats y ifCyd Ldwy ij dsl ntZ

xkft;kckn : कविनगर थाने में होली एंजल पब्लिक स्कूल के प्रबंधन, डायरेक्टर और प्रधानाचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दसवीं कक्षा के बच्चे को एडमिशन देने और पूरे साल फीस व अन्य खर्च वसूलने के बाद भी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं दिलाया गया, जिसके चलते उसका एक साल खराब हो गया। बता दें कि इसी हफ्ते विभिन्न स्कूलों के 94 बच्चों ने इसी स्कूल पर एडमिट कार्ड न देने का आरोप लगाया था, जबकि सोमवार को स्कूल में ही पढने वाले नौ बच्चों के अभिभावकों ने भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड न देने का आरोप लगाया था। होली एंजल पब्लिक स्कूल में इसी सत्र में नौ बच्चों का ट्रांसफर दूसरे स्कूल से हुआ था। इनमें लोहियानगर निवासी सानिध्य भी शामिल है। सानिध्य के पिता पवन गोयल ने बताया कि नौवीं पास करने के बाद सानिध्य का ट्रांसफर उन्होंने कविनगर के होली एंजल पब्लिक स्कूल में कराया था।

डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा

xkft;kckn : कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इस माह के अंत तक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी सरकारी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारी को दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श विद्यालयों में सुसज्जित भवन, शौचालय, चारदीवारी, पंखे, कंप्यूटर, डस्टबिन, रैंप सहित अन्य के लिए निर्देश दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि 308 विद्यालय आदर्श विद्यालय बनाये गए हैं जबकि 162 विद्यालय अभी शेष रह गए हैं। जिलाधिकारी विकास कार्यों एवं योजनाओं को तय समय और गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।समीक्षा बैठक में हाउड्क्षसग के 41 केस मिलने पर रजिस्ट्री कराने का नोटिस दे देने के लिए कहा गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन, परियोजना निदेशक डीआरडीए एसके त्रिपाठी, समाज कल्याण अधिकारी परितोष श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

clrij lFkyh ç/kku dks e[;e=h us fd;k lEekfur

xkft;kckn : मुरादनगर क्षेत्र के गांव बसंतपुर सैंथली की प्रधान को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गांव में उत्कृष्ट कार्य करने और स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रधान को सम्मानित किया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में वह मेरठ मंडल से सम्मानित होने वाली इकलौती प्रधान हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला ग्राम प्रधानों और स्वच्छाग्रहियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वच्छ शक्ति नामक इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं केंद्रीय

मंत्री उमा भारती ने स्वच्छ भारत अभियान, बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ अभियान आदि में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला ग्राम प्रधानों और स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया। क्षेत्र के गांव बसंतपुर सैंथली की प्रधान अर्णिमा त्यागी को भी इस सम्मान से नवाजा गया। वह मेरठ मंडल की इकलौती महिला ग्राम प्रधान हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने इस सम्मान से नवाजा। बता दें कि क्षेत्र के गांव बसंतपुर सैंथली में प्रधान अर्णिमा त्यागी ने कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। गांव में पहुंचने पर स्वच्छ भारत अभियान का खासा असर देखने को मिलता है। गांव को पूरी तरह ओडीएफ कर दिया गया है। गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा गांव के प्राथमिक विद्यालयों की सूरत भी पूरी तरह बदल दी गईं। गांव का प्राथमिक विद्यालयों को देख ऐसा लगता है कि मानों यह प्राइवेट स्कूल हों।

vrjk"Vh; efgyk fnol ij vk;kftr fd, x, dk;Øe

xkft;kckn : कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को आकांक्षा समिति और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहीं जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अग्रणी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं समाज को आगे बढ़ाने का काम

कर रही हैं। समारोह में डीएम ने 10 अलग–अलग क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और 11 महिला ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। इसमें महिला थाना प्रभारी सुनीता मलिक, महिला अस्पताल की सीएमएस डा. दीपा त्यागी, जूडो कोच शिवानी, एडीआइओएस ज्योति दीक्षित, पूनम शर्मा सहित अन्य शामिल रहीं। समारोह में पूनम शर्मा, पुनीता त्यागी, अंजू जैन, संध्या त्यागी, अर्चना शर्मा, डा. मंजू आदि मौजूद रहीं।

pkbYM ykbu dkvkfMZuVj d lkFk bfnjkiije Fkku e vHkærk

xkft;kckn ।। इंदिरापुरम क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी के लापता होने के मामले में परिजनों के साथ थाने पहुंचे चाइल्ड लाइन कोआर्डिनेटर के साथ थाने में अभद्रता की गई। शिकायत देकर कोआर्डिनेटर ने जल्द कार्रवाई की अपील की तो थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे अभद्रता की। उन्होंने तुरंत सीओ और बाल कल्याण समिति की सदस्य को बताया। आला अधिकारियों के निर्देश पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। चाइल्ड लाइन के कोआर्डिनेटर आरिफ ने बताया कि 28 फरवरी को एक 14 वर्षीय लड़की संदिग्ध हालात में घर से लापता हो गई थी। परिवार में सिर्फ मां और भाई ही है, जोकि पुलिस थाने में जाने से डर रहे थे। उन्होंने 1098 पर कॉल कर चाइल्ड लाइन को सूचना दी, जिसके बाद बुधवार को वह इंदिरापुरम थाने में पहुंचे। लिखित शिकायत देकर उन्होंने कहा कि यह केस चाइल्ड लाइन के पास भी दर्ज है। परिजनों की परेशानी का हवाला देकर जल्द कार्रवाई को कहा।

efgykvk dk fl[kk, vkRej{kk d xj

xkft;kckn : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन में पुलिस द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए साथ ही मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में सेल्फ डिफेंस विशेषज्ञ परवेज अली ने महिलाओं को अपने साथ रहने वाले सामान क्लचर, मोबाइल फोन, चश्मा, दुपट्टे व पर्स द्वारा किस तरह से आत्मरक्षा की जाए इसका प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्राएं व महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर एसएसपी हरिनारायण ङ्क्षसह ने कहा कि सेल्फ डिफेंस के गुर सीखने के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेता है। इसलिए महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज के समय में समाज में अग्रणी भूमिका में रहकर प्रशंसनीय काम कर रही हैं। इसके लिए महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

4097 Nk=k u 27 ldM e jpk bfrgkl

xkft;kckn : आईटीएस संस्थान के मुरादनगर, मोहन नगर और ग्रेटर नोएडा स्थित परिसर में छात्रों ने एक साथ माउथवॉश कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया। 4097 छात्रों ने पहले प्रयास में ही निर्धारित समय से पहले 27 सेकेंड में कीर्तिमान रच गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में नाम दर्ज करा लिया। आयोजन का मुख्य उद्देष्य त्मुख को साफ रखने के लिए जागरूकताय फैलाना था। इसमें कुल 4166 छात्रों ने भाग लिया। विभिन्न कारणों से इसमें 4097 छात्रों को चुना गया। इस कीर्तिमान में मुरादनगर स्थित परिसर में 1321, ग्रेटर नोएडा स्थित परिसर

में 1384 और मोहन नगर स्थित परिसर में 1392 छात्रों ने भाग लिया। हालांकि यहां बनाया गया रिकार्ड टाइप टू का है, जिसमें कई जगह एक साथ कार्यक्रम कराए गए थे। एक जगह का रिकार्ड (टाइप वन) अभी भी फिलिपिंस की एक संस्था के नाम है, जहां एक साथ 2046 छात्रों ने माउथ वॉश किया था।

mÙkj jsyo d egkçc/kd u fLXuy od'k,i dk fujh{k.k fd;k

xkft;kckn : उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विश्वेश चौबे ने बुधवार को गाजियाबाद स्थित सिग्नल वर्कशॉप का निरीक्षण किया। वह यहां वर्कशॉप में नए बने रिटायरिंग रूम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यह रिटायरिंग रूम सिग्नल वर्कशॉप में बाहर से आने वाले रेलवे स्टॉफ के ठहरने के लिए बनाया गया है। बुधवार सुबह करीब 10.40 बजे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विश्वेश चौबे स्पेशल रेल गाजियाबाद कोटगांव फाटक के पास स्थित सिग्नल वर्कशॉप में पहुंचे। यहां रिटायरिंग रूम के उद्घाटन के बाद उन्होंने पूरे वर्कशॉप में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अच्छे कार्यों के लिए जहां स्टाफ की सराहना की। वहीं कई जगह कमियां देख जरूरी दिशा–निर्देश भी दिए। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के आए अफसरों के साथ स्थानीय अफसर भी मौजूद रहे।

EDITORIAL

India's economy returns to its growth pattern

The Indian economy has recovered from the disruptions caused by the invalidation of high value currency notes in November 2016 (demonetisation) and the implementation of the unified Goods and Services Tax in July 2017. The benefits of the first can be debated and so, hypothetical as the exercise may be, one can't help wondering where the economy would have been without it. The second was necessary, and has definite medium- and long-term benefits. The numbers released on February 28 by the Central Statistics Office show that key macroeconomic indicators are back (well, almost back) to where they were in late 2016. For instance, the growth in Gross Value Added or GVA was 6.7% in the three months ended December 31, up from 6.2% in the preceding three months. It is inching closer to the 7.2% growth seen in the three months ended 30 September 2016. Similarly, the manufacturing sector (the worst hit by the implementation of GST) grew 8.1% in the three months ended December 31, up from 6.9% in the preceding three months.

The numbers, and the return of growth, were expected. The Indian economy grew by 7.2% in the three months ended December (GDP), beating analyst estimates of 7%. Since January, high-frequency data (data measured and released every month, such as sales or various products), have shown that the Indian economy is back to its growing ways. Earnings of Indian companies for the three months ended December show the same trend and the fastest growth in a year. The most heartening thing about the latest data is that investment growth is back. Gross fixed capital formation grew at 12% in the three months ended December, up from just under 7% in the preceding three months. Investment growth (or demand) and consumption growth are the two big pillars of GDP growth. The worrying thing for India is that the government is running out of tinder (its fiscal deficit at the end of December was almost 114% of the full year number) ,which means its ability on both the consumption and the investment side of the equation will now be limited, and private consumption growth is slowing.

Still, barring an oil-price shock, and despite the strange case of Indian exports (which should be growing strongly but aren't), it is evident that the Indian economy, which will end March as a $2.6 trillion dollar one, is back where it was ahead of demonetisation. That we should be celebrating a 7.2% growth is a reflection of how bad the past 15 months have been. If things stay the same on all fronts, we can look forward to a better 2018-19 and 2019-20.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

Girl's body found with injury marks

NOIDA: A 15-year-old girl was found dead at her rentedaccommodation in Sector 33 on Saturday. The deceased, Kallo, had injury marks on her throat and is suspected to have been strangulated. The police suspect the role of her family members behind the alleged murder. The victim lived with her family members in a shanti. Her father Dalveer is a sanitation worker with Noida Authority. Akhilesh Tripathi, SHO, Sector 24 police station, said that on Saturday evening that the police had received information that a young girl was dead. "A police team reached the spot and took the body in custody and launched an investigation into the matter," he said.

cd e vjck #i, dk ?kkVkyk vkj fuxjkuh

euh"kk Hkkxo

i tkc नेशनल बैंक में अरबों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद सरकार की नींद टूटी है। ऐसे घोटालों को कैसे रोका और कर्ज डकार कर भागने वालों से निपटा जाए, यह सवाल सरकार और बैंक प्रबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। फिलहाल फौरी तौर पर सक्रिय हुए वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को पंद्रह दिन की मोहलत देते हुए ऐसे जोखिमों से बचाव के लिए अपनी व्यवस्था चाकचौबंद करने को कहा है। अब अगर पचास करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई कर्ज संदेह के घेरे में आता है तो बैंक को तत्काल इसकी सूचना केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को देनी होगी। बड़े घोटालों से पार पाने के लिए सीबीआइ के अलावा प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय जैसी एजंसियां भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। जो ताकतवर लोग कर्ज लेकर चंपत हो गए हैं, उनसे वसूली के लिए नया कानून बनाने की भी तैयारी है। इस कानून में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजंसियों को और सशक्त बनाने का प्रावधान है। यह कानून बनने के बाद ऐसे फरार घोटालेबाजों के खिलाफ मुकदमों के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी, जो इन मामलों का निपटारा करेंगी।

शुरू में नीरव मोदी–मेहुल चोकसी का घोटाला ग्यारह हजार चार सौ करोड़ रुपए का था, लेकिन अब यह बारह हजार सात सौ करोड़ को पार कर गया है। रोटोमैक कंपनी का साढ़े तीन हजार करोड़का घोटाला और सिंभावली शुगर मिल में सौ करोड़ से ऊपर का घपला भी उजागर हुआ। अभी ऐसे और घोटाले सामने आएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दरअसल, ये घोटाले बैंकों के कुप्रबंधन और गहरे पैठे भ्रष्टाचार की देन हैं। बैंक अफसरों की मदद से कर्जखोर कैसे लूट मचाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला इसका उदाहरण है। पीएनबी का उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी सात साल से जिस संवेदनशील पद पर जमा था, उस पर तीन साल से ज्यादा किसी को नहीं रखा जा सकता, जबकि तीन बार शेट्टी के तबादला आदेश रद्द हुए। जाहिर है, शेट्टी की पहुंच ऊपर तक रही होगी और शीर्ष स्तर पर भी इससे कोई अनजान नहीं रहा होगा। अब वित्त मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं उनमें शीर्ष स्तर के प्रबंधन की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। इन घोटालों ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को भी कठघरे में ला दिया है। लालफीताशाही संस्कृति में जकड़ा वित्त मंत्रालय इस बात से आंखें मूंदे रहा कि बैंकों में अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। हाल में एक आरटीआइ पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया था कि उसे विजय माल्या के कर्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माल्या के बारे में देश की जनता, बैंक, अदालतें सबको पता है, लेकिन वित्त मंत्रालय अनजान है। सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है?

d,jikjV vkj fdlku e Qdl D;k

nfonj 'kek

पंजाब के बठिंडा में एक किसान को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया। उसकी गलती बस यह थी कि वह बैंक से लिया दो लाख रुपये का कर्ज नहीं लौटा सका था। कुछ हफ्ते पहले हरियाणा के एक किसान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई और उसे 9.80 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए। उसने सिंचाई के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए छह लाख रुपये का कर्ज लिया था। सीबीआई ने जब रोटोमेक के मालिक विक्रम कोठारी को 3,695 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान न करने से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था, तब मैं सोच रहा था कि क्या अदालत उन्हें सजा सुनाए जाने के साथ ही उन पर इस राशि के बराबर जुर्माना करेगी। दरअसल विभिन्न तबके के लोगों के लिए व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। एक और मामले को देखिए। हरियाणा के कैथल के 96 वर्षीय रामदिया के लिए हर महीने मिलने वाली 1,600 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन ही एकमात्र सामाजिक सुरक्षा थी। मगर इस उम्र में पिछले कुछ महीने से उन्हें इससे वंचित कर दिया गया था। 2006 में उन्होंने पचास हजार रुपये का जो कर्ज लिया था, उसके भुगतान के लिए बैंक ने निर्दयता पूर्वक उनकी सारी पेंशन ही ले ली, जोकि उसी बैंक के जरिये उन्हें मिलती थी। वृद्धावस्था पेंशन के सिर्फ वही ऐसे लाभार्थी नहीं है, जिन्हें उनकी इस जीवनरेखा से काटकर अलग कर दिया गया। यह बैंकिंग के कायदों के विपरीत है। मगर गरीब और वंचित तबके के लोगों के साथ बैंकिंग व्यवस्था इसी बेरहमी से पेश आ रही है। दूसरी ओर बैंकों ने धनी दिवालिया लोगों के लिए अलग नियम बना रखे हैं। उनके साथ नरमी से पेश आया जाता है और यहां तक कि रिजर्व बैंक ने भी उनके द्वारा लिए गए कर्ज को जायज ठहराया है, जोकि अब फंसा कर्ज बन चुका है। खबरों के मुताबिक 30 सितंबर, 2017 को अपनी मर्जी से दिवालिया होने वाले 9,339 लोग थे, जिन्होंने बैंकों के कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये के कर्ज लौटाने से इन्कार कर दिया था। जानबूझकर दिवालिया होने वाले ऐसे लोग या कंपनियां क्षमता होने के बावजूद कर्ज का भुगतान नहीं करना चाहते। इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था और आर्थिक नीतियां उन्हें सुरक्षा की एक छतरी प्रदान करती हैं। विगत चार वर्षो में कॉरपोरेट कर्ज बहुत तेजी से डूबा है। 2013 में खराब कर्ज की राशि 28,417 करोड़ रुपये थी, जो कि बढ़कर सितंबर, 2017 में 1.1 लाख करोड़ रुपये हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि बैंकों के दो नियम हैं, एक कॉरपोरेट के लिए दूसरा किसानों के लिए। बैंक अक्सर कर्ज न चुकाने वाले किसानों के नाम और फोटो तहसील कार्यालय में चस्पा कर देते हैं, लेकिन मैंने बैंकों को कभी कॉरपोरेट दिवालिया लोगों के नाम इस तरह उजागर करते नहीं देखा। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक कई बार सर्वोच्च न्यायालय से जानबूझकर दिवालिया होने वाले लोगों के नाम उजागर न करने का आग्रह कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे निवेशकों में गलत संदेश जाएगा। यदि जानबूझकर दिवालिया होने वाले 9,339 लोगों के नाम और तस्वीरें बैंकों की शाखाओं में और सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे औद्योगिक संगठनों के सूचना पट्टों पर चस्पा कर दिए जाते, तो मुझे पक्का यकीन है कि इससे वे शर्मिंदा होते और यह कदम कवच का काम करता। लेकिन ऐसे लोगों को मिल रही सुविधाएं और रियायतों के कारण फंसा कर्ज (एनपीए) बढ़ता जा रहा है और उन्हें किसी तरह का पश्चाताप भी नहीं है, जो यह दिखाता है कि किस तरह से बैंकिंग का पूरा ढांचा केवल अमीरों और ताकतवर लोगों की सेवा कर रहा है। नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने पंजाब नेशनल बैंक से 11,400 करोड़ रुपये (अब यह राशि और बढ़ गई है) हड़प लिए और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागकर सुरक्षित पनाहगाहों में पहुंच गए हैं, तो यह दिखाता है कि बैंकिंग नियामक का भय सिर्फ आम आदमी के लिए है।

Ghaziabad couple found dead in bathroom after Holi party

GHAZIABAD: Hours after extended Holi celebrations with family and neighbours, an executive at a cellular services company and his wife, who worked with an MNC, were mysteriously found dead in the bathroom of their Indirapuram flat on Friday. Police are clueless on how the couple died. The postmortem report puts the cause of death as "uncertain". The two were found naked, with strips of tablets to treat blood pressure strewn near the bodies, police said. "Their viscera have been preserved for now and will be sent for forensic tests in Agra," said Sachin Malik, the SHO of Indirapuram. The police are yet to receive any written complaint. Neeraj Singhania, 38, a deputy general manager

with Matrix Cellular (International) Services Limited, and his wife Ruchi, 35, who worked with a US-based IT company in Noida, lived with his parents, younger brother and sister in a 3BHK flat in Indirapuram's Gyan Khand 1. They have a five-year-old daughter. The police said the couple had celebrated Holi through the day on the roof of their flat and returned around 6pm. When they did not respond to repeated knocks on the door around 9.30pm, Neeraj's younger brother looked through a slit in the window and found his sister-in-law's leg protruding from the bathroom. Sensing something amiss, the family broke open the door. "They found the couple lying on the floor of the bathroom without any clothes. An ambulance was called and they were rushed to a private hospital, where they were declared dead on arrival. Their bodies, however, did not have any injury marks," said Rakesh Kumar Mishra, the circle officer of Indirapuram. "Ruchi's parents, too, had come from Vaishali to celebrate Holi in the Indirapuram flat. The birthday of Neeraj's father Prem Prakash Singhania and the marriage anniversary of his parents-in-law fall on March 2. The family had gathered to celebrate the occasion," Mishra added. Police sources said the celebrations had started early in the morning for the Singhanias. A roof-top party was organised and attended by relatives as well as neighbours. Abhishek Das, one of the neighbours, said: "Around 9.45pm, I saw an ambulance parked in front of our building. I rushed downstairs and saw Neeraj being taken on the stretcher and paramedics giving CPR (cardiopulmonary resuscitation) to Ruchi. I heard a doctor tell the family that the two were already dead and it was up to them to take them to the hospital. Neeraj's family decided to go to the hospital."

Complaint against us false: Jaypee Infratech Limited

NOIDA: Jaypee Infratech Limited on Monday issued a statement claiming that the complaint filed against its officials by an individual was not based on facts. The management also approached Noida Authority for relief. The company told the Authority that some individuals were giving false police complaints as part of their efforts to grab parcel of land and in the process maligning the image of company. "On March 3, once again they tried to grab the land, for which Noida Authority had given an affidavit in Allahabad high court that the land transferred to JIL was from within the acquired land of Noida Authority.

Two youths nabbed after shootout in Dadri

GREATER NOIDA: Two persons were arrested after a shootoutin Dadri on Friday night. The arrested have been identified as Shoaib (24), an original resident of Kalyanpuri in Delhi, and Sameer (22), a resident of Kavi Nagar in Ghaziabad. Around 11.30pm, the police received a tip-off about the movement of two criminals on a bike in Nagla Nainsukh village. "A police team reached the spot and started checking all vehicles. When they signalled the two persons on a bike to stop, they

tried to speed away after opening fire at the police team. The cops retaliated and the two got injured in their left legs.

No admit card, 94 students left in lurch in GZB

GHAZIABAD: Scores of Class X and XII students along with their parents on Sunday staged a protest at a school in Kavi Nagar over "cancellation" of their registration by the CBSE ahead of the board exams, which starts from March 5. The students alleged that as the schools where they are actually enrolled do not offer Class X and XII, their registration for the CBSE examination has been done through Holy Angel's Public School by their respective school management through an "internal" agreement. But, when they approached Holy Angel's Public School to get their admit cards, the school management said they were unaware of such an agreement. Seema Tyagi, president of Ghaziabad Parents' Association, said, "The future of 94 students studying in four different schools of the city is at stake. They have been left in the lurch by both—the schools where they are actually enrolled and the Holy Angel's School." Anurag Pandey, a Class X student of Maharaja Convent School, Vijay Nagar, said: "Our school lied to us that it has recognition till Class X. Every time we raised a query about our admit cards, the school management told us that we would get them at the appropriate time. It was only a few days back we were told about the arrangement with Holy Angel's School.." Siddharth Jain, owner of Holy Angel's Public School, refuted the allegations. "These 94 students are not from my school. I do not know why the management of other schools are taking my name. The parents of the students do not have any document to prove that they are registered with us."

UP farmer saves drowning Delhi cop, family after car plunges in canal

MEERUT: The heroic actions of a farmer here saved the lives of a Delhi police inspector, his wife and son after their car plunged into a canal on Tuesday evening near a village. Mahesh Chand Sharma, 50, an additional sub inspector in Delhi Police, his wife Savitri and son Rajat Gautam were returning to Ghaziabad from Sardhana, and had taken the road adjacent to the Upper Ganga canal, as it had less traffic. Near the village of Rohta, while trying to avert a collision with another vehicle, the car fell into the canal and the three passengers began to drown. Balram Singh, 28, a farmer from Patholi village nearby, was

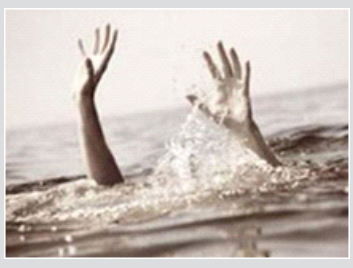

passing the stretch on his motorcycle when he witnessed the car fall into the canal. He immediately flagged down a passing vehicle, which fortunately had a length of rope in it, and jumped into the canal. Singh told TBC on Wednesday: "The car hit the wall of the canal and plunged into the water. I could see none of the three people could swim, and the canal is about 12 feet deep in that stretch. So I jumped in with the rope, which I was lucky to find in the car I flagged down. I I made them catch hold of the rope and pulled them back to the bank." Subhash Atri, station officer of Rohta police station, said, "The timely action of Singh saved the life of the Delhi Police officer and his family. Later, we reached the spot and got the car out with the help of a crane." The family of Sharma or the police officer could not be contacted as their phones got damaged by water. On Wednesday, divisional commissioner Prabhat Kumar met Singh and praised his exemplary actions which saved the family.

Security guard beats up resident in Ghaziabad

GHAZIABAD: A 33-year-old resident of a high-rise apartment in Rajnagar Extension was hit on the head by a security guard posted there on Sunday night over the refusal of giving money for buying alcohol. The victim, Puneet Goyal, a share broker and a resident of Gaur Cascades society, was standing at a distance from the society's main gate and talking to one of his friends on Sunday around 11.30 pm. Suddenly, security guard Durgesh Vashishtha, who was apparently drunk, approached them and inquired about the reason why they were standing there. He then demanded Rs 100 from each of them and an argument between the two sides ensued. Angered by the refusal, he beat up Goyal using a stick, who immediately called up the police. A non-cognizable offence report (NCR) under section 323 (voluntarily causing hurt) was subsequently registered on Monday and the accused was produced before a magistrate.

GDA fined Rs 1 crore for raising EWS flat price 'unilaterally'

GHAZIABAD: Fair trade regulator Competition Commission of India (CCI) on Wednesday imposed a fine of over Rs 1 crore on Ghaziabad Development Authority (GDA) for abuse of its dominant position by unilaterally raising the prices of dwelling units under the economically weaker section (EWS) category in Pratap Vihar housing scheme. The matter dates back to 2008 when GDA floated its Pratap Vihar EWS scheme. The price of each dwelling unit under the said scheme was initially fixed at Rs 2 lakh, but in 2015 on completion of the project, the price of each unit was raised to Rs 7 lakh. A beneficiary of the scheme, Satyender Singh, moved the CCI, alleging that GDA acted in "an arbitrary and unilateral manner" in raising the price. In its order, the CCI held that GDA acted in contravention of Section 4(2)(a)(i) of the Competition Act, 2002, which says 'there shall be an abuse of dominant position if an enterprise, directly or indirectly, imposes unfair or discriminatory condition in purchase or sale of goods or services'. The CCI, in its order, said the GDA under the said scheme acted arbitrarily and unilaterally "without any enabling provision either in the brochure of the scheme or allotment letter", and hence a penalty of Rs 1,00,60,794 was imposed. The CCI also handed out a cease-and-desist order against GDA, which means it wants the development authority to immediately stop indulging in such activities. The GDA, on its part, said there was indeed "a costing error" committed by then GDA executive engineer, but insisted it was not intentional. "We will appeal against the order in higher appellate authority," SS Verma, superintending engineer, GDA, told TBC. While explaining GDA's position, Verma said when the EWS scheme for 348 flats in Pratap Vihar was conceived in 2008, there were many factors which had not been taken into account while fixing the price to Rs 2 lakh. "Price was fixed under the tenure of RL Saroj, who was the then executive engineer of GDA, and when the matter came to light, an departmental inquiry was initiated against him. When the project was competed in 2015, it was realised that costing norms were not followed in deciding the price like contingency and overhead charges were not included. So, the prices were revisited and then hiked to Rs 7 lakh," he added.

Groom killed in celebratory firing in Delhi, accused absconding

NEW DELHI: A bridegroom was killed after suffering bullet injury during celebratory firing in Delhi's Seemapuri area on Tuesday late night. The deceased, identified as 23-year-old Deepak, was hit by a bullet on his head from behind. He was rushed to the Guru Tag Bahadur (GTB) Hospital where doctors declared him dead at around 2 am. The accused is a distant relative of the deceased and is absconding since the incident. Read this story in Hindi "As per the preliminary probe, Deepak suffered bullet injury from behind. Police are searching for the accused," told Deputy Commissioner of Police Nupur

Prasad. Police are questioning people present there at the time of the incident. CCTVfootages from nearby cameras are also being scanned to get more clues about the incident. Several teams have been dispatched to Ghaziabad in search of the accused.

Two-hour snarl on Noida e-way after truck hits bus

NOIDA: Commuters had to battle snarls on the expressway for nearly two hours after a private bus collided with a container truck on the Greater Noida-Noida carriageway of the Expressway during peak hours on Monday morning. The accident occurred around 8.15 am on the stretch between the Advant building and Pari Chowk. The driver and conductor of the truck and the bus suffered minor injuries but around 35 passengers of the bus were not hurt. According to an eyewitness, the accident occurred when the driver of the container apparently missed the cut towards Tilapta in Dadri and tried to turn his vehicle back towards Pari Chowk. "In an attempt to take a wrong turn, the driver hit the speeding bus which was travelling from Gorakhpur to Delhi on the same carriageway," an officer from Knowledge Park police said. Ram Dayal Gupta, the owner of the bus, said: "We have reached a compromise with the other party." Commuters travelling from Greater Noida to their offices in Noida and Delhi said traffic moved at an extremely slow pace as it took time for the traffic police and civil police to remove the bus from the spot.

EPCA to focus on industrial pollution in NCR

NEW DELHI: The SC-mandated pollution control board, EPCA, on Wednesday decided that it will focus on reducing industrial pollution in NCR this year. While lifting the 'severe and very poor' category interventions under the Graded Response Action Plan (GRAP) in NCR, EPCA, at a meeting with authorities in NCR, enquired what was being done to move industries to cleaner fuels. Environment Pollution Control Authority head, Bhure Lal, also pointed out that many polluting industries in Delhi, which had claimed to have moved to the

outskirts or outside on paper, continued to function within the city. Currently, EPCA is working on identifying these 'non-conforming' industries. EPCA had flagged the issue of these illegal industries at earlier meetings as well, but the Delhi environment department and Delhi Pollution Control Committee (DPCC) were unable to act against these units because of legal loopholes. The officials who attended the meeting said they were aware about these industries in the 'nonconforming areas' (areas not meant for industrial activity according to the master plan), but DPCC cannot shut them immediately as the law prescribes issuing of a notice first. The notice would be as good as recognising them to be legal, the officials said However, Bhure Lal pointed out that, "You can always act against them under the provisions of the Air Act. If an industry is polluting the air, you have the right to seal it under the Act irrespective, of whether it's in conforming or non-conforming areas." SM Ali, special secretary, informed EPCA that the Delhi government this year has managed to convince industrial associations to convert to PNG, but mentioned nothing about their plans to deal with the ones working in non-conforming areas. EPCA member Sunita Narain said "Hotspots like Bhiwadi and Ghaziabad remain extraordinarily polluted. Industries should be top priority for the Central Pollution Control Board (CPCB) and state pollution control boards."

हेल्प लाईन नंबर

गाजियाबाद प्रशासन

डीएम -	2824416
आवास -	2820106
एडीएम (सिटी) -	2828411
एडीएम (प्रशासन) -	2827016
सिटी मजिस्ट्रेट -	2827365
आयकर विभाग -	2714144
पासपोर्ट कार्यालय -	2721779

पुलिस अधिकारी

एसएसपी -	2821120, 2820157
पुलिस अधीक्षक नगर -	2854015
पुलिस अधी. यातायात -	2829520
क्षेत्राधिकारी प्रथम -	2733070
क्षेत्राधिकारी द्वितीय -	2791769
क्षेत्राधिकारी तृतीय -	9958776662
क्षेत्राधिकारी चतुर्थ -	2898131
साहिबाबाद -	2630691
कविनगर -	2711843
लिंकरोड़ -	2770310
इंदिरापुरम -	2275858
लोनी -	2600097

जीडीए

उपाध्यक्ष जीडीए -	2791114
जीडीए सचिव -	2790891

अस्पताल

सी.एम.ओ. -	2710754
सी.एम.एस. -	2730038
आपातकालीन -	2850124
कोलम्बिया एशिया -	3989896
यशोदा अस्पताल -	2750001-04
गणेश अस्पताल -	4183900
संतोश अस्पताल -	2741777
सर्वोदय अस्पताल -	2701694
जि0 अस्पताल(एम्बुलेंस) -	2730038

नरेन्द्र मोहन अस्पताल (एम्बुलेंस) 2735253
यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस) 2701695
पुष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल 4188000
पुष्पांजली मेडिकल सेन्टर 43075600

बीएसएनएल

आदेश कुमार (जीएम) -	2755777

अग्निशमन विभाग

नगर कन्ट्रोल रूम -	2734906
कन्ट्रोल रूम-कोतवाली -	2732099
जिला कन्ट्रोल रूम -	2766898

पुलिस स्टेशन

कोतवाली -	2732088
सिहानी गेट -	2791627
कविनगर -	2711843
विजयनगर -	2740797
लिंकरोड -	9999993066
इंदिरापुरम -	2902858
साहिबाबाद -	9999993020
लोनी -	2600097
अग्निशमन विभाग -	2732099
	9818702101
रेलवे इन्कवायरी -	131

नगर निगम

नगरायुक्त -	2790425, 2713580

विद्युत विभाग

मुख्य अभियंता -	2821025

पूछताछ

रेलवे कस्टमर -	2797840, 139
रिजर्वेशन -	8888
रोडवेजइन्कवायरी -	2791102

प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।

Phone No.: 0120-2850800, 2850297

Sector 137 residents demand police station amidst increased crime spate

NOIDA: Citing deteriorating law and order situation in sector 137, residents took to streets on Sunday and demanded for a police station in the area. While kids held posters stating 'We feel unsafe due to kidnapping,' women held placards saying 'We feel unsafe due to chain snatching and men held posters saying 'We feel unsafe due to mobile snatching.' With over 70,000 residents living in the sector, the overall sentiments were a feeling of insecurity in the area due to increased incidents of mobile/ chain snatching, car jacking, breaking of car glasses, kidnapping theft etc and a non-active police / administration. "Due to recent spurt in criminal activities and ineffectiveness of policing we held a protest near Ajnara Daffodils Society in the sector against police administration on Sunday. The purpose of the protest was to ensure a police station for the sector along with a police chowki and cameras to monitor movement of criminal activities and deter crimes in the area" said Abhisht Gupta, a resident of sector 137. Currently crimes in the sector are handled by sector 144 police chowki which is clearly unable to cater to increased incidents of crime as per residents with their limited manpower. The residents of the sector have been complaining of the problem since long. "Due to recent increase in criminal activities in sector 137, resident fear to roam in their vicinity even in the broad day light. Crimes like car theft, mobile snatching, chain snatching, kidnapping, attempt to kidnap, breaking car glass and stealing valuables have taken place in the broad day light," said Gipta.

Bull death in Greater Noida triggers stir by vigilantes

GREATER NOIDA: A bull was found dead in a field in Jarchawith an injury mark on the back, triggering a protest by cow vigilantes who filed a police complaint against four persons for allegedly killing the animal. The police said a primary investigation had revealed that the allegations against the four persons were not true and they had been named in the complaint to "settle personal scores". Ved Nagar, a member of the Gau Raksha Dal, filed a police complaint naming local residents Kamru Zama and Alisen, and two unknown youths. Nagar said he reached the village around 8pm on Friday after receiving information that a bull had allegedly been killed. He said a local farmer named Sudheer, who was herding cattle back home from the field, had seen four persons chasing the bull with country-made guns. "They were unable to get hold of the bull. The accused took out a gun and fired at the animal. It collapsed on the field." Shailendra Pratap Singh, the SHO of Jarcha police station, said the cause of the bull's death was not yet clear. "Nobody had seen how it died. There is an injury mark on its back. Based on the complaint, we had initially registered a case under Sections 3 and 8 of the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955, and Sections 3 and 11 of The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, against the four persons."

Noida plans to make stilt parking a must for all

NOIDA: In order to streamline parking in the city, the Noida Authority on Thursday invited suggestions from the public on its proposal to change the building bylaws. As per the proposal, the Authority wants to make it mandatory for all individual residential plot owners to have stilt parking to accommodate their vehicles. In addition, all group housing developers will have to provide one parking space for every 50 square metres as compared to the current norm of one parking space for every 80 square metres of space bought by residents.

Noida Class VII boy arrested for 'raping' 4-year-old girl

NOIDA: A Class VII student has been apprehended for allegedly raping his neighbour's four-year-old daughter after luring her to his house in Sector 73. The 14-year-old boy was produced before the JuvenileJustice Board on Tuesday, which sent to a remand home in Phase II. Police said the crime took place around 4pm on Monday when both the teenager and the girl were alone at home. Seeing the girl alone, the boy lured her with toffees to his house and then sexually assaulted her. While the parents of both the boy and the girl were at work at the time, her elder sister had also stepped out of the house for a while. Both the families lived opposite each other in rented accommodation in a village in the sector, cops said. The girl returned home on her own in the evening, but complained of pain in her private parts when her mother came back from work. She finally narrated her ordeal to her parents after being coaxed by her mother. Cops were soon called. The girl was taken to district hospital for a medical examination, where it was confirmed that she was sexually assaulted. Subsequently, the boy was picked up. "The parents of both the children are migrant labourers," Uday Ram, a Sarfabad resident, told TBC. Sector 49 SHO Pankaj Pant said the boy was at home as he had not gone to his school in Sarfabad on Monday. "After getting information, we sent the girl for medical examination which confirmed carnal intercourse.

Probe sought into 2015 GDA building bylaws

GHAZIABAD: A section of residents has approached the Ghaziabad Development Authority seeking an inquiry into the process adopted by officials in 2015 to identify 13 areas for implementing amended building bylaws. The GDA had selected the areas after an order pertaining to the amendment of building bylaws exclusively for Ghaziabad was issued in 2014 by the UP housing department. According to the order, people could build four floors and stilt parking lot if they owned plots measuring between 112 and 2,000sqm. The plot owners were required to pay 10% of the floor area ratio (FAR), according to the prevailing circle rates. The fees were meant to undertake expansion and augmentation of civic infrastructure, including sewer lines, water pipelines, roads and electricity cables. Santosh Yadav, who was the then vice-chairperson of GDA, had said the amended bylaws were meant to develop residential areas in Ghaziabad on a par with those in Delhi. A seven-member panel formed by Yadav had identified certain sectors and blocks in nine colonies. Eight of these colonies, including Indirapuram, Kaushambi, Shalimar Garden, Govindpuram and Rajendra Nagar, were approved by the GDA in January 2015 for implementing the bylaws. Another five colonies, including Vaishali, Brij Vihar and Lajpat Nagar, were added to this list by the GDA in April 2015.

fr : ifr ckykth Økfudy] xkft ;kckn

के प्रकाशन के संबंध में सूचना

फार्म 4

(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थान	:	गाजियाबाद
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	बी.एफ.एल. इंफोटेक लिमिटेड
पता	:	सी–9, सेक्टर–3 नोएडा, डिस्ट्रिक गौतमबुद्ध नगर यूपी
4. प्रकाशक का नाम	:	धीरज कुमार
क्या भारत का नागरिक हैं	:	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
पता	:	282, सराय नजर अली, एम.एम.जी. हॉस्पिटल के पीछे, गाजियाबाद यूपी 201001
5. संपादक का नाम	:	धीरज कुमार
क्या भारत का नागरिक हैं	:	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
पता	:	282, सराय नजर अली, एम.एम.जी. हॉस्पिटल के पीछे, गाजियाबाद यूपी 201001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	मनीषा भार्गव, 282, सराय नजर अली, एम.एम.जी. हॉस्पिटल के पीछे, गाजियाबाद यूपी 201001

मैं धीरज कुमार भार्गव एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

fnukd % 4 ekp 2018

g@
/khj t dekj Hkkxo
ikdk'kd

gkml VDl dh nj c<kus vkj cps g, ?kjk ij dj yxkus dh r;kjh

xkft ;kckn : बढ़ रहे खर्चों को देखते हुए नगर निगम आय में इजाफा करने के लिए हाउस टैक्स वृद्धि करेगा। बुधवार को मेयर आशा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में 773 करोड़ 65 लाख 80 हजार रुपये का प्रस्तावित बजट मंजूर हो गया। इस शर्त के साथ कि आय बढ़ाने के लिए हाउस टैक्स में वृद्धि की जाए। सर्वे करार उन इलाकों के घरों पर टैक्स लगाया जाएगा, जहां निगम की सुविधाएं मुहैया करा रहा है। किसी कारण से वह इलाके अब तक टैक्स के दायरे से बाहर रह गए हैं। इस बार बजट में नगर निगम ने सड़कों के सुंदरीकरण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। पहली बार इसके लिए मद का सृजन किया गया है। जिसमें दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नगर निगम के प्रस्तावित बजट में हाउस टैक्स से 55 करोड़ रुपये की अनुमानित आय निर्धारित की गई है। पिछले वित्त वर्ष में भी इस मद में इतनी ही अनुमानित आय रखी गई थी। जिसकी तुलना में जनवरी तक निगम 31.19 करोड़ रुपये ही हाउस टैक्स वसूल पाया। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक दो वर्ष में 10 प्रतिशत हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रावधान हैं। नीति का अध्ययन करने के बाद वह दर बढ़ा देंगे। अगर, ऐसा संभव नहीं हुआ तो हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा जाएगा। यहां मंजूरी मिलने के बाद शासन की मंजूरी ली जाएगी।शहर में अनाधिकृत रुप से चल रही डेयरियों पर सदस्यों ने कहा कि डेयरी संचालकों के चालान काटे जाएं। नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी को बताया कि पिछली बार आधा वर्ष बीतने के बाद पार्किंग के ठेके छोड़े गए थे। जिस कारण आय कम हुई है। इस बार मार्च अंत तक ठेके छोड़ दिए जाएंगे। पार्षदों ने बैठक में लाइसेंस आय का ब्योरा नगर आयुक्त से मांग लिया।

v,uykbu gk xbl g ifjogu foHkkx ls lcf/kr VDl vkj Qhl dh 0;oLFkk

xkft ;kckn : संभागीय परिवहन विभाग में वाहन–4 साफ्टवेयर शुरू होने के बाद सभी तरह की फीस और टैक्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए अधिकारियों ने पंजीकृत वाहनों के मालिकों को सूचना देना भी शुरू कर दिया है। इंदिरापुरम में फर्जी एआरटीओ के पकड़े जाने के बाद अधिकारियों ने किसी भी तरह की चेकपोस्ट होने से इंकार किया है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की फीस और टैक्स ऑनलाइन जमा होगी। अधिकारियों का कहना है कि संभागीय परिवहन कार्यालय गाजियाबाद का कोई भी काउंटर कहीं भी स्थापित नहीं है। जहां पर विभाग से संबंधित फीस को जमा कराया जाए। दरअसल, बृहस्पतिवार को इंदिरापुरम में वाहन मालिकों से एआरटीओ बनकर फीस और टैक्स वसूलने वाले नटवरलाल मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद अधिकारियों ने सूचना को जारी किया। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह का कहना है कि वाहन–4 शुरू होने के बाद सभी प्रकार की फीस और टैक्स ऑनलाइन लिया जा रहा है। लोगों को इस बारे में जागरूक रहना चाहिए, संभागीय परिवहन विभाग की कोई भी चेकपोस्ट या काउंटर नहीं हैं।

ç/kkue=h vkokl ;kstuk d ¶yV cukus dk e¶r e feyxh tehu

xkft ;kckn % प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने को ग्राम समाज और नगर निकायों मुफ्त जमीन उपलब्ध करानी होगी। इसे लेकर शासन ने सहमति दे दी है। शासन स्तर की एक बैठक में जीडीए के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। जमीन की किल्लत और अधिक लागत का दर्द प्राधिकरण अधिकारियों ने बयां किया। उन्हें बताया गया कि जल्द मुफ्त में जमीन मुहैया कराने का शासनादेश जारी होने जा रहा है। शासन से गाजियाबाद में इस योजना के तहत 9000 फ्लैट बनाने का लक्ष्य दिया गया है। एक फ्लैट 22.66 वर्ग मीटर में बनेगा। जिसमें दो कमरे, रसोई, दो बालकनी और शौचालय होगा। उस परिसर में पार्क समेत कई सुविधाएं देनी होंगी। यह शर्त भी है कि आवंटी से महज दो लाख रुपये जाएंगे। ढाई लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार अंशदान देगी। जीडीए और आवास विकास परिषद को यह फ्लैट बनाने हैं। इनके सामने दिक्कत थी कि अपनी जमीन देकर फ्लैट तैयार करने में लागत अधिक आ रही है। इससे इन संस्थाओं पर आर्थिक भार बढ़ जाएगा। जिसे देखते हुए मांग की गई थी कि ग्राम समाज और नगर निकायों से मुफ्त जमीन मुहैया करा दी जाए। जिसके लिए शासन तैयार हो गया है। 2022 तक फ्लैट तैयार कर आवंटियों को सौंपने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत फ्लैट बनाने के लिए कई जगह भूखंड चिह्नित किए गए हैं। प्राधिकरण की ओर से लोनी, निवाड़ी, फरीदनगर, डूंडाहेडा सहित अन्य क्षेत्रों मे ग्राम समाज के साथ ही एलएमसी की जमीन को चिह्नित किया गया है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ में 1440 फ्लैट बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल चुकी है। मधुबन–बापूधाम में 852 फ्लैट बनाने की मंजूरी के लिए डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। निवाड़ी में नगर पंचायत की जमीन पर फ्लैट बनाने को शासन हरी झंडी दिखा चुका है। जीडीए के मुख्य अभियंता विवेकानंद सिंह का कहना है कि कांशीराम योजना की तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट बनाने के लिए प्राधिकरण को मुफ्त भूखंड मिल सकता है। शासन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जल्द इस संबंध में शासनादेश जारी हो जाएगा।

xhrktfy lfefr us efgykvk dk fd;k lEekfur

xkft ;kckn : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बुधवार को राजनगर स्थित आइएमए भवन में गीतांजलि वेलफेयर एजुकेशनल समिति ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप दुबे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि समय के साथ–साथ भारतीय नारी के कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। संस्था की सचिव वंदना चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के काम केवल गृहस्थी संभालने तक सीमित नहीं हैं बल्कि महिलाओं की उपस्थिति हर क्षेत्र में है।

lijVd dk 30 uocj rd lkr vkofV;k dk nuk gkxk dCtk

xkft ;kckn : समय पर फ्लैट का कब्जा न देने के मामले में नेशनल कंज्यूमर डिसप्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) ने सुपरटेक लिमिटेड को आदेश दिया है कि सात आवंटियों को 30 नवंबर तक कब्जा दिया जाए। विलंब के लिए मुआवजे के रूप में कब्जे के लिए निर्धारित की गई तिथि से अब तक आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। आवंटियों को देय मुआवजा शेष राशि में समायोजित किया जाएगा। इसके बावजूद कब्जा देने में देरी होती है तो बिल्डर को दस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। निर्मल्या वेलफेयर सोसायटी ने 2015 में एनसीडीआरसी में शिकायत की थी कि सुपरटेक लिविंगस्टोन क्रॉसिंग रिपब्लिक में 26 आवंटियों को समय से कब्जा नहीं दिया।

xkft ;kckn e cuxk n'k dk igyk jktuhfrd if'k{k.k dsUn] dok;n rst

xkft ;kckn % देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में बनाने की कवायद तेज हो गई है। सीएनडीएस उत्तर प्रदेश जल निगम को इसके निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इसे बनाने में 221 करोड़ 44 लाख 90 हजार रुपये की लागत आएगी। नगर आयुक्त आयुक्त ने कार्यकारिणी सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने बजट में इसके लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है। राजनगर एक्सटेंशन में नंदी पार्क के पास 30 हजार वर्ग मीटर भूमि पर इसे बनाया जाएगा। यहां निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को कामकाज से जुड़ा प्रशिक्षण देने के लिए रिफ्रेशमेंट कोर्स संचालित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी पहल की है। देश की राजधानी के करीब होने के नाते गाजियाबाद को यह केंद्र खोलने के लिए उचित पाया गया। नगर विकास विभाग ने नगर निगम से न्यूनतम दस हजार वर्ग मीटर जमीन मांगी थी। निगम ने राजनगर एक्सटेंशन के पास सिहानी गांव में 54 हजार वर्ग मीटर जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव शासन को भेजा था। उसमें से 30 हजार वर्ग मीटर में इसे बनाने का निर्णय हुआ है। यहां भवन निर्माण के अलावा प्राकृतिक झील और स्मारक भी बनाई जाएगी। जन प्रतिनिधियों को देश, विदेश की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासतों से रूबरू कराया जाएगा। जनता से सामंजस्य स्थापित करने के गुर सिखाए जाएंगे। योजना बनाने के तरीके और नीतियों के बारे में सिखाया जाएगा।

BUREAU OFFICE
PRATEEK BHARGAVA
Bureau Chief
5, Ashok Vihar, 3rd Floor, GMS Road, Nr. Ballupur Chowk, Dehradun.
Mobile: +91 8130640011
Email: prateekb@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release and Advertisements

BUREAU OFFICE
VIKRAM KUMAR
Bureau Chief
12/516, Friends Co-operative Society Vasundhra, Ghaziabad (UP)
Mobile: +91 8130640077
Email: vikram@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release and Advertisements

Printed and Published by Dheeraj Kumar Bhargav at B.F.L Inrotech Ltd, C-9, Sector-3 Noida, Distt. Gautam Budh Nagar and Published at 282, Sarai Nazar Ali, behind MMG Hospital Ghaziabad (U.P.) 201 001. Editor: Dheeraj Kumar, Resident Editor : Manisha Bhargava** Email: editor@tbam.co.in **(RNI. No) : UPBIL / 2009 / 28691 Postal Registration No. UP/GBD-80/2016- 18.** Advertisement : Ph. No. : 0120-2850800, 2850297, Fax : 0120-4561000 at 67, 1st Floor, Richpal Puri, Hapur Road, Ghaziabad (U.P.)** Responsible for selection of News under the PRB Act. Reproduction in any manner, electronic or otherwise in whole or in post without prior written permission is prohibited.